

● वर्ष-6
● अंक-61
रायपुर, शनिवार
10 अक्टूबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-३ रु.

॥ संगछध्वम् संवदध्वम् ॥

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> अंडर-1 7 व अंडर-1 9 दोनों ...



मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण रद्द भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले संशोधन कानून को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण फिर से 14 प्रतिशत रहेगा। साथ ही सरकारी भर्तियों में लंबे समय से रोके गए 13 प्रतिशत पदों पर अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती एजेंसियों को यह प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करनी होगी। हालांकि, ओबीसी पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले संशोधन कानून को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण फिर 14 प्रतिशत रहेगा। अदालत ने सरकारी भर्तियों में रोके गए 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश दिए हैं। मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग

(एमपीपीएससी), कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) और अन्य भर्ती एजेंसियों को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ओबीसी पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण 29 सितंबर 2022 से कई सरकारी भर्तियों में 87=13 प्रतिशत का फार्मूला अपनाया जा रहा था। इसके तहत 87 प्रतिशत पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी, जबकि बाकी 13 प्रतिशत पदों को अंतिम निर्णय तक रोककर रखा गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन पदों पर अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता खुल गया है।

ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का मामला कई वर्षों तक कानूनी विवाद में रहा। इस दौरान सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू करने और लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं अपनाई गईं।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों की



भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तीन महीने की समय-सीमा में लंबित 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना प्रशासन के सामने चुनौती होगी। लंबे समय से परिणाम और नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इस आदेश से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, ओबीसी पक्ष की ओर से फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में आगे की कानूनी कार्रवाई पर भी नजर रहेगी।

विवाद की प्रमुख तारीखें

मार्च 2019 : तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अध्‍यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की पहल की। अगस्‍त 2019: संशोधन कानून लागू हुआ। इसके बाद कानून की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

201-2022 : विवाद के बीच सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को लेकर कानूनी अड़चने बनी रही।

29 सितंबर 2022: 87.13 प्रतिशत के फार्मुले के तहत 87 प्रतिशत पदों पर भर्ती आगे बढ़ाने और 13 प्रतिशत पदों को विवाद के निपटारे तक अलग रखने की व्यवस्‍था अपनाई गई।

2023-2025 : विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में होल्‍ड पदों और नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी रखा।

5 अगस्‍त 2026 : हाईकोर्ट में अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।

काँकरोच के खिलाफ उतरी लाल हिट

नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को काँकरोज जनता पार्टी (सीजेपी) के बड़े प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को राजधानी में एक नए संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। ‘हिट जनता पार्टी’ के बैनर तले जनपथ पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं का विरोध किया। इस संगठन का नाम भी अपने आप में चर्चा का विषय है। माना जा रहा है कि इसका नाम कीड़े-मकोड़े मारने वाले एक लोकप्रिय ब्रांड से प्रेरित है और इसे सीजेपी के जवाब में व्यंग्यात्मक अंदाज में सामने लाया गया है।

प्रदर्शन में संगठन की ओर से शामिल हुए अयान भटनागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का



इस्तेमाल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अगर कोई किसी बाहरी व्यक्ति को भी बुरा-भला कहता है, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री तो हमारे अपने परिवार का हिस्सा हैं। उनके खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना गलत है। हमारे नायकों, जवानों और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का अपमान भी बंद होना चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

हिट जनता पार्टी के

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि व्यवस्था में बदलाव की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए विरोध का मौजूदा तरीका सही नहीं है। संगठन ने जोर दिया कि अपनी बात रखने और असहमति जताने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसका कहना है कि विरोध के नाम पर हिंसा, अभद्र भाषा या पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को किसी भी हालत में सही नहीं दहराया जा सकता।

इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, मतपत्र से चुनाव की मांग

नयी दिल्ली। नौ अक्टूबर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि मुर्मू ने उनकी बातों को खारिज नहीं किया तथा इससे जुड़े सबूत मांगे जो उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तुण्मूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय समेत 10 नेताओं ने इस गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विपक्षी नेता सोमवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत से भी “वोट चोरी” के विषय पर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रपति से मिलने के बाद खरगे ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दलों ने पिछले चार दिनों से जारी आंदोलन के तहत राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी बात रखी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद खरगे ने संवाददाताओं से कहा, “हम वोट चोरी के बारे में बताने के लिए राष्ट्रपति के पास गए थे। हमने उनके समक्ष अपनी बात रखी और उनसे आग्रह किया कि ईवीएम को हटाकर मतपत्रों से चुनाव कराया जाए।” खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के आरोपों के संबंध में सबूत मांगे हैं और विपक्ष उन्हें सबूत उपलब्ध कराएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति का रुख नकारात्मक नहीं था और उन्होंने आश्वासन दिया ।

तमिलनाडु उपचुनाव : सीएम विजय की पार्टी ने जीतों दोनों सीट

तमिलनाडु । तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी तमिलनाा वेट्टे कड्गम (टीवीके) ने मदुरैतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव जीत लिए हैं। मरगथम कुमारवेल और सत्यभामा ने अपने-अपने डीएमके पार्टी के प्रतिद्वंद्वियों को हराया। इस जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश का माहौल है। अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई है। मरगथम कुमारवेल ने मदुरैतकम सीट 17,554 वोटों के अंतर से जीती, जबकि सत्यभामा ने धारापुरम में 10,196 वोटों से जीत हासिल की। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में डीएमके दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद एआईएडीएमके का स्थान रहा। राज्य सरकार के मंत्रियों ने इन दोहरी जीत को टीवीके सरकार के पिछले चार महीनों के कामकाज पर जनता की मुहर बताया है। राज्य की प्रमुख पार्टियों के बीच उपचुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखा गया था। इस नतीजे ने विजय सरकार को एक नई राजनीतिक गति प्रदान की है।

ईंडि ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं हुई शिव सेना यूबीटी

मुंबई।शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर बताया है कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होगी। पार्टी नेताओं संजय राउत और अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों में व्यस्तता को इसकी वजह बताया। हालांकि, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन दिया है। सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया है कि उसके प्रतिनिधि शुक्रवार रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव से जुड़े पहले से तय कामों में व्यस्त रहना है। हालांकि, पार्टी ने विपक्षी गठबंधन और इस मुद्दे पर उसके अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया है। इंडिया ब्लॉक के नेता, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज्‍न में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के सिलसिले में राष्ट्रपति से रात 8 बजे मिलने वाले हैं।

अखिलेश यादव का दावा, 2027 में बदलेगी योगी सरकार योगी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 का विधानसभा चुनाव अयोध्‍या से लड़ने की सलाह दी। विपक्ष के पूर्व नेता राम गोविंद चौधरी के पैतृक गांव बलिया में बोलते हुए यादव ने कहा कि अगर आदित्यनाथ को अयोध्‍या के लोगों का समर्थन मिलने का भरोसा है, तो उन्हें इस मंदिर शहर से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए यादव ने साफ़ किया कि इसे चुनौती न समझें। यह उन्हें दी गई एक राजनीतिक सलाह थी। अगर अयोध्‍या के लोगों के साथ उनका तालमेल इतना अच्छा है, और अगर उन्होंने कहा है कि 15 दिनों में सच सामने आ जाएगा, तो उन्हें उनके बीच से ही अगला चुनाव लड़ने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्‍या के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन शहर को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान और मान्यता मिल सकती थी। यादव ने कहा कि अयोध्‍या के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। उन्होंने मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगाए गए आरोपों की आलोचना करते हुए कहा, मंदिर के बाहर बैठा भिखारी भी चढ़ावा नहीं चुराता।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

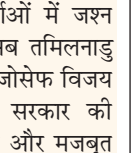
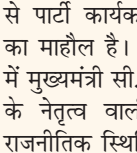
प्रमुख समाचार

असम, बंगाल और पुदुचेरी में जीत पर पीएम मोदी ने जताया मतदाताओं का आभार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में भाजपा-एनडीए उम्मीदवारों की जीत के बाद मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी सराहना की। मोदी ने कहा कि ये नतीजे भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे के प्रति लोगों के जुड़ाव को दिखाते हैं। उन्होंने पुदुचेरी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोगों का समर्थन गठबंधन को और मजबूती देता है। उन्होंने असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम व रेजिनगर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि इन नतीजों से पता चलता है कि लोग भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों का भी इस जीत में महत्व है।

नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा को मिली जीत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हस्सीरानी रथ को 1,22,753 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से विजयी घोषित किया गया। जहां रथ को 1,64,427 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के मिलन प्रधान 41,674 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, सीपीआई के शांति गोपाल गिरी 5,779 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के अली मोहम्मद साबे मिराज खान 1,607 वोट हासिल करके चौथे स्थान पर रहे। ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक तुण्मूल कांग्रेस पांचवें स्थान पर रही और उसे सिर्फ 853 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया तुण्मूल कांग्रेस इस बार नंदीग्राम में चुनावी दौड़ में शामिल नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आखिरी समय में अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की।



अनुसूचित जाति -जनजाति के लिए न्याय को सुदृढ़ करना एक संवैधानिक गारंटी

रामदास अठावले

एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव इस भरोसे पर टिकी होती है कि प्रत्येक नागरिक गरिमा, समानता और सुरक्षा के साथ जीवन यापन कर सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह प्रतिबद्धता मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों, प्रभावी कानूनों और उत्तरदायी संस्थाओं के माध्यम से ठोस रूप लेती है। इसलिए, भारत सरकार ने अत्याचारों की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क को लगातार मजबूत किया है।

इस फ्रेमवर्क का आधार दो प्रमुख कानून हैं- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर ओसीटी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी(पीवए)/एसटीटी)। वर्षों से इन कानूनों को विधायी संशोधनों, बेहतर राहत और पुनर्वास प्रावधानों, विशेष न्यायिक तंत्रों, शिकायत-निवारण प्रणालियों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के जरिए सुदृढ़ किया गया है।

जाति-आधारित अत्याचारों के प्रति संवेदनशील समुदायों की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने के

लिए एससी/एसटी अधिनियम, 1989 में उल्लेखनीय विकास हुआ है। इस दिशा में एक बड़ा कदम 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए संशोधनों के जरिए उठाया गया। इन संशोधनों में अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों (एक्सक्यूटिव स्पेशल कोर्ट्स) की स्थापना और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रावधान किया गया। अधिनियम में कई नए प्रकार के अत्याचारों को भी शामिल किया गया, जिससे एससी और एसटी समुदायों को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा का दायरा व्यापक हुआ। उतना ही महत्वपूर्ण पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों से जुड़ा एक समर्पित अध्याय जोड़ना भी

था। पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों के प्रति राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को और सुदृढ़ किया गया-यह स्वीकार करते हुए कि न्याय केवल मामले के पंजीकरण और मुकदमे की सुनवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें प्रभावित लोगों की सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद, 14 अप्रैल 2016 को एससी/एसटी नियम, 1995 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने

राहत और पुनर्वास फ्रेमवर्क को मजबूत किया, अत्याचार के 47 अपराधों के लिए निर्धारित राहत राशि में वृद्धि की और पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को समय पर वित्तीय सहायता के वितरण पर जोर दिया।

समय पर न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करना 20 अगस्त 2018 को एससी/एसटी अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से और भी महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए। इस संशोधन ने इस कानून के तहत मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी

व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को भी हटा दिया गया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था- प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार से जुड़े अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन में बाधा नहीं बननी चाहिए। एससी/एसटी नियम, 1995 में 27 जून 2018 को भी संशोधन किया गया, जिसने मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एसिड हमले, संपत्ति के नुकसान और कानून के दायरे में आने वाले अन्य अपराधों के मामलों में राहत प्रावधानों को और मजबूत किया। ये सुधार इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करते हैं कि

कानून को केवल कागजों पर ही मजबूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जब कोई पीड़ित सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाए, तब उसे सुलभ और संवेदनशील भी होना चाहिए। एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 217 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। यह अधिनियम संवैधान्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, उन जिलों में सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने का भी प्रावधान करता है।

शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्यों?

बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डबल बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। बता दें, कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णतः दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं। यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ज्ञात हो, कि जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए पद का आरक्षण किया गया था, अंधमूक बाधिर के अलावा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को भी आरक्षित पदों का लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पूर्णतः दृष्टिबाधित को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।

आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी व ससुराल वालों को कोर्ट ने सुनाई सजा



धमतरी। धमतरी में नया इतिहास रचा गया है। धर्मांतरण के दबाव में एक युवक ने जान दे दी थी। मामले में कोर्ट ने युवक की पत्नी के साथ सास-ससुर और दोनों सालियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है।

पूरा मामला अजुंनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीह गांव का है। 6 सितंबर 2024 को लिनेश साहू नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि लिनेश की पत्नी, उसके सास-ससुर और दो सालियां लगातार ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। लिनेश बार-बार मना करता रहा,

लेकिन दबाव खत्म नहीं हुआ। तंग आकर उसने पहले वाट्सअप-इंस्टाग्राम में स्टेट्स रखकर सारी समस्या बताई, फिर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, और अब घटना के लगभग एक साल बाद अप सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी करुणा बाई साहू के साथ ससुर राजकुमार साहू, सास गौरी साहू, सालियां किरण और कनिष्का साहू को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल का कठोर कारावास और पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले में लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति थे।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

धमतरी में गरबा के साथ पहली बार लाइव भजन जैमिंग का आयोजन

धमतरी। नवरात्र पर्व के साथ ही धमतरी में गरबा की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सिहावा रोड स्थित शांति वाटिका में नवरंग 6 10 का आयोजन होने जा रहा है। इस बार गरबा सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां भक्ति के साथ देशभक्ति और छत्तीसगढ़ के साथ अलग-अलग राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। नवरंग गरबा की इस बार की खास बात यह है कि आयोजन में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों और गरबा खेलने वालों का गंगाजल छिड़काव और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए धार्मिक आस्था और पारंपरिक माहौल को विशेष महत्व दिया जाएगा। वहीं, अलग-अलग दिनों में निर्धारित थीम के अनुसार प्रतिभागी अपनी वेशभूषा और गरबा प्रस्तुति से आयोजन को खास बनाएंगे। आयोजन में धमतरी के युवा ही सेलिब्रिटी के रूप में नजर आएंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी निर्धारित थीम के अनुरूप वेशभूषा में गरबा की प्रस्तुति देने के लिए सीमित समय मिलेगा।

एनएच 53 रेहटीखोल चेक पोस्ट पर गांजा की बड़ी खेप पकड़ी

महासमुंद। महासमुंद जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे-53 पर रेहटीखोल चेक पोस्ट के पास नाकेबंदी कर 560 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये है। पुलिस ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपजन में धमतरी के युवा ही सेलिब्रिटी के रूप में नजर आएंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी निर्धारित थीम के अनुरूप वेशभूषा में गरबा की प्रस्तुति देने के लिए सीमित समय मिलेगा।



पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र नंबर का एक आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन क्रमांक MH 18 BG 7546 में भारी मात्रा में गांजा भरकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंधोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस टीम ने एनएच-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन का इंतजार किया। कुछ समय बाद अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिर के बताए गए नंबर की गाड़ी

पहुंची। पुलिस ने वाहन को रोककर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ के दौरान दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। गाड़ी में रखे कैंरेट के नीचे बोरियां छिपाकर रखी हुईं

मिलीं। बोरियों की जांच करने पर उनमें गांजा मिला। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में बोरियों को खुलवाकर गांजे का वजन कराला। कुल 16 बोरियों में 560 किलोग्राम गांजा मिला। हर बोरी में करीब 35 किलो गांजा था। पुलिस ने बताया कि तस्करी ने गांजे को कैरेट के नीचे बोरियों में छिपाया था, ताकि सामान्य जांच के दौरान उस पर आसानी से नजर न पड़े। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान अजय रविन्द्र पवार (30 वर्ष),

बड़ी साजिश को देने वाले थे अंजाम, लेकिन जवानों की घेराबंदी में दबोचे गए 2 नक्सली

अब एनआईए कोर्ट ने 10-10 साल की सुनाई सजा



डेटोनेटर, तार का बंडल, एक स्विच, प्लास्टिक रस्सी के तीन बंडल, छरों के दो पैकेट, करीब एक किलोग्राम लोहे के टुकड़े, दो पाइप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था।

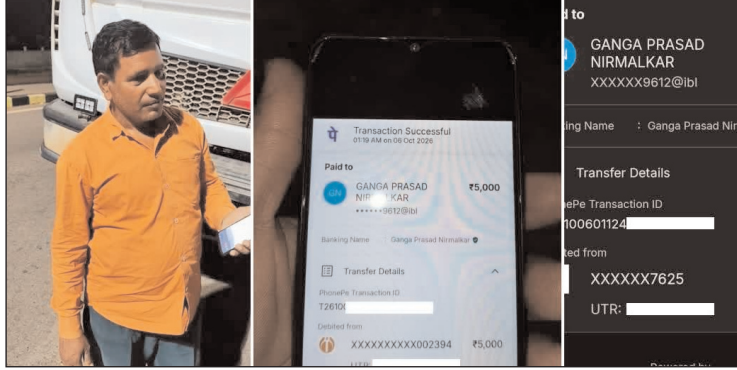
इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण प्रगति पर

एक ही छत के नीचे संचालित होंगे विभिन्न विभागों के कार्यालय, आमजन को शासकीय कार्यों के लिए मिलेगी बेहतर सुविधा

खैरागढ़। सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत नवगठित खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विकासखण्ड खैरागढ़ में प्रस्तावित इस भवन के निर्माण के लिए 15 मार्च 2024 को 1875.58 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग, संभाग खैरागढ़ द्वारा किया जा रहा है।

संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण का उद्देश्य जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एकीकृत परिसर में उपलब्ध कराना है। भवन के पूर्ण होने के बाद विभिन्न शासकीय विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित होंगे। इससे जिले के नागरिकों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाने के लिए अनावश्यक आवागमन नहीं करना पड़ेगा और शासकीय योजनाओं, सेवाओं एवं विभागों कार्यों से संबंधित जानकारी और प्रक्रियाओं के लिए एक ही परिसर में सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए भवन में विभागीय कार्यालयों के एक



साथ संचालित होने से प्रशासनिक समन्वय को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच समन्वय से नागरिकों से जुड़े कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। साथ ही, शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा।

जिले के नागरिकों के लिए संयुक्त जिला कार्यालय भवन केवल एक कार्यालय परिसर नहीं, बल्कि विभिन्न शासकीय सेवाओं तक के पूर्ण होने से प्रमाण-पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, विकास योजनाओं सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के लिए नागरिकों को व्यवस्थित कार्यालयीन सुविधा

उपलब्ध होगी। इससे समय और श्रम की बचत के साथ शासकीय सेवाओं तक पहुंच भी अधिक सुविधाजनक होगी। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गठन के बाद प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दिशा में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह कार्यालय परिसर जिले की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप शासकीय कार्यों के संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित केंद्र के रूप में विकसित होगा। भवन के पूर्ण होने के बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायी अधोसंरचना मिलने के साथ आमजन को भी विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ एक ही परिसर में अधिक सुविधाजनक रूप से मिल सकेगा।

किसानों का 24 घंटे से नेशनल हाइवे पर प्रदर्शन

कवर्धा। जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कबीरधाम पहुंचे और रायपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया। शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़े किए जाने से आवागमन बाधित हो गया है, केवल एम्बुलेंस को आने-जाने दिया जा रहा है। गुरवार को भी किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इसके कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। किसानों के प्रदर्शन पर प्रशासन नजरे बनाई हुई है। गुरवार को प्रशासनिक टीम ने प्रदर्शनस्थल पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की थी, लेकिन यह बेमतीजा रही किसानों की प्रमुख मांगों में जिले के दोनों शक्कर कारखानों में गन्ना उत्पादन बढ़ाना, गन्ने के बोनस में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, सुतियापाट जलाशय का विस्तार, बिजली बिल कम करना और पूर्व सरकार के धान बोनस की राशि जारी करना सहित 23 मांगें शामिल हैं। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।

निवासी सोनबरक्षी, थाना एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) और स्वराज महाजन (25 वर्ष), निवासी कसोदा आडगांव, थाना कसोदा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) के रूप में बताई। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी गांजे को ओडिशा के बरहमपुर क्षेत्र से वाहन में लोड कर महाराष्ट्र के जलगांव जिले की ओर ले जा रहे थे। पुलिस अब इस मामले में गांजे की तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 560 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई है, जब्त किया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन, जिसकी कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

बिलासपुर में गरबा ड्रेस में लड़कियों ने सिगरेट का धुआं उड़ाया, पिस्टल लहराई

बिलासपुर। शहर में गरबा की ड्रेस पहनकर सिगरेट पीने और हाथ में नकली पिस्टल दिखाकर वीडियो बनाना कुछ युवतियों और युवकों भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद, भारतीय संस्कृति के अपमान और समाज में गलत संदेश फैलाने के आरोप में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है।

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। बताया कि एक युवती व उसके कुछ सहयोगियों ने गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन किया और पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर गरबा टिकट/मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

वीडियो को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया गया। अशोभनीय ओर गलत चीजों को महिमामंडित करने का आरोप लगाया गया। इससे समाज में युवाओं पर गलत असर पड़ने की आशंका जताई गई है। मामले में एएसपी पंकज



कुमार पटेल ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 196, 299 एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर ज्यादा से ज्यादा राशि से बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है। पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें तथा आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन आगे प्रसारित न करें। साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार के नाम पर न किया जाए। जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो।

हाइवा वाहनों से अवैध वसूली के स्क्रीन शॉट वायरल

धमतरी। जिले में रेत से भरे हाइवा वाहनों को रोककर कथित अवैध वसूली का मामला चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से शहर में हाइवा रोकने और उनसे एक व्यक्ति के अकाउंट नंबर में पैसे ट्रान्सफर कराए जा रहे हैं। सोशल



मीडिया पर इसका एक वीडियो और कुछ ऑनलाइन लेनदेन के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं। इनमें शहर के नहरनाका चौक पर वाहन रोककर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो में एक

हाइवा चालक ने अपनी गाड़ी का नंबर दिखाते हुए बताया कि वह बालोद का रहने वाला है और उसके साथ वसूली हुई है। वहीं, सोशल मीडिया पर सामने आए यूपीआई ट्रंज़ेक्शन के स्क्रीनशॉट में अलग-अलग क्रिस्तों में रकम के लेनदेन का दावा किया जा रहा है। वायरल दावों के मुताबिक, कुल रकम 25 से 30 हजार रुपये के आसपास बताई जा रही है। ऑनलाइन भुगतान से जुड़े विवरण में ट्रॉसफर अकाउंट नाम गंगा प्रसाद निर्मलकर दिखा रहा है। आखिर वह कौन है और किस विभाग या किसी

दल से संबंधित है इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। दरअसल मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने बिना वैधानिक अधिकार के मालवाहक वाहनों को रोककर पैसे वसूले हैं, तो यह जांच का विषय है। मामले को लेकर जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि फोनपे और गूगल पे के जरिए लेनदेन किए जाने की जानकारी सामने आई है। किसी भी वाहन को बिना प्राधिकृत अधिकार के रोकना विधिसम्मत नहीं है। यदि मामला उनके संज्ञान में आता है, तो संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि हाइवा को किससे रोकना, पैसे किस वजह से लिए गए और कथित वसूली के पीछे कौन था ?

बोधघाट क्षेत्र में ग्रामीणों से मिले कांग्रेस नेता

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटेी के नवनियुक्त प्रभारी सुखदेव भगत दंतेवाड़ा दौरे पर रहे। गीदम पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटेी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मध्वे, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, सह-सचिव विजय जांगिड़, डॉ। एस ए सम्पत कुमार, मोहन मरकाम, जरिता लैतफलांग, लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने मां दंतेक्षरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और मां दंतेक्षरी का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश और वस्तर की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। मां दंतेक्षरी की पूजा के बाद कांग्रेस प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का काफिला कांग्रेस भवन पहुंचा, जहां जिला कांग्रेस कमेटेी की महत्वपूर्ण बैठक में जिलेभर से पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन

बेमेतरा। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ ने राज्य के पारंपरिक कृषि ढांचे, गो-वंश संरक्षण और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। संघ ने राज्य के किसानों की गंभीर समस्याओं और मांगों को लेकर सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कुल 13 प्रमुख बिंदु हैं। बेमेतरा जिला में बिजली कटौती को किसानों ने मुख्य मुद्दा बनाया है। बेमेतरा में सौंपे गए मांग पत्र में दिए गए 13 बिंदु गोवर्धन योजना लागू करना भारतीय किसान संघ द्वारा दिए गए गोवर्धन योजना प्रस्ताव को तुरंत लागू किया जाए एवं जी-राम-जी योजना को गो-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन से जोड़ा जाए। 2। रुकी हुई राशि का भुगतान धान खरीदी वर्ष 2022-23 को किसानों की रुकी हुई 1700 करोड़ की राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। 3। लागत और बोनस का लाभ पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार द्वारा की गई 258 (117+69+72) की वृद्धि का लाभ बोनस के रूप में किसानों को दिया जाए। सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए। 4। धान

खरीदी की घोषणाएं 15 नवंबर से 15 जनवरी तक होने वाली धान खरीदी में, प्रति तौल अधिकतम 40 किलो 700 ग्राम लेने का आदेश जारी किया जाए (जिसका आश्वासन पूर्व में कैबिनेट मंत्री द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को दिया गया था)। 5। बाढ़ क्षतिपूर्ति में व्यवस्था हाल ही में आई बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में किसानों की फसलों को भारी हानि हुई है। शासन तुरंत सर्वे कराकर किसानों की क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था करे। 6। टोकन व्यवस्था में सुधार धान खरीदी में टोकन व्यवस्था को सुधारा जाए। बड़े किसानों को पांच टोकन, लघु किसानों को 3 और सीमांत किसानों दो टोकन दिए जाएं, जिससे धान खरीदी के समय अनावश्यक दबाव न बने। 7। गन्ने के मूल्य में वृद्धि गन्ना फसल के मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाए एवं इसे भी कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए। 8। सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी अरपा-पैंसाझार जैसी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में गति लाई जाए एवं पूरी हाईडैम जैसी नई परियोजनाओं (जिनमें सिंचाई की बहुत अधिक संभावनाएं हैं) को तुरंत स्वीकृत किया जाए।

ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव पर बहस तेज

नीरज कुमार दुबे

भारतीय चुनावी राजनीति में इन दिनों ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस फिर तेज है। विपक्षी दलों का एक वर्ग लगातार मांग कर रहा है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। हाल में इंडिया ब्लॉक ने भी बैलेट पेपर की वापसी की मांग दोहराई है और चुनाव आयोग के खिलाफ राजनीतिक अभियान तेज किया है। लेकिन इस बहस के बीच एक असहज सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर बैलेट पेपर ही चुनावी निष्पक्षता की गारंटी है, तो हाल में बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों की व्याख्या विपक्ष किस तरह करेगा ? हम आपको बता दें कि असम के सिलचर में 3 अक्टूबर को नगर निगम के पहले चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान हुआ। परिणाम में भाजपा ने 42 में से 32 सीटें जीतीं और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने दो सीटें हासिल कीं। कांग्रेस को केवल दो सीटें मिलीं, जबकि छह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। यानी बैलेट पेपर वाले चुनाव में भी भाजपा-नीत छद्म ने दो-तिहाई से अधिक सीटें जीत लीं। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्वङ्कूरुपर सवाल उठाने वाली राजनीति में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो परिणाम अलग होगा। सिलचर का परिणाम कम-से-कम इतना जरूर बताता है कि मतदाता पेर अपने आप किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में परिणाम नहीं बदल देता। मतदाता जिस राजनीतिक दल को समर्थन देना चाहता है, वह अपना समर्थन मतदान की किसी भी व्यवस्था में व्यक्त कर सकता है। इसी संदर्भ में इस साल हुए पांच विधानसभा चुनावों यानि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के पोस्टल बैलेट आंकड़ों की भी चर्चा होनी जरूरी है। निर्वाचन आयोग के चुनाव नतीजों वाले पोर्टल पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में श्वङ्कूरुवोटों के साथ पोस्टल वोटों का भी अलग विवरण दर्ज है। आप इनका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा और एनडीए को अच्छी खासी संख्या में पोस्टल बैलेट के जरिये भी मत मिला था। असम में तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को पोस्टल बैलेट में मजबूत समर्थन मिला था। पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र रहे जहां भाजपा उम्मीदवारों को सैकड़ों पोस्टल वोट मिले और वे परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। हम आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट मुख्यतः चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और कानून के तहत पात्र अन्य श्रृणियों के मतदाताओं से जुड़े होते हैं। इसलिए इनके आधार पर पूरे राज्य की जनता की राजनीतिक पसंद का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़े एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा करते हैं। सवाल उठता है कि यदि किसी दल का तर्क है कि मतदान की मशीन यानि ईवीएम ही उसकी हार का कारण है, तो उसे उन चुनावों और निर्वाचन क्षेत्रों को भी देखना चाहिए जहां काजग पर वोट पड़े और फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। देखा जाये तो विपक्ष के सामने वास्तविक राजनीतिक चुनौती केवल श्वङ्कूरुपर सवाल उठाना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि मतदाता लगातार चुनाव मुद्दों, नेतृत्व और संगठनात्मक विकल्पों को प्राथमिकता दे रहा है। चुनाव आयोग या किसी संवैधानिक संस्था की आलोचना करने का लोकतांत्रिक अधिकार विपक्ष के पास है। यदि कहीं चुनावी प्रक्रिया में ठोस अनियमितता का प्रमाण है, तो उसकी जांच और सुधार की मांग भी पूरी तरह जायज है। लेकिन हार के हर परिणाम को पहले से ही संस्थागत साजिश मान लेना और संगठन, उम्मीदवार, जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दों तथा राजनीतिक रणनीति की समीक्षा से बचना लोकतांत्रिक राजनीति के लिए स्वस्थ रास्ता नहीं है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

17. चार्वाक-दर्शन

गतांक से आगे...

न कोई आत्मा है और न कोई पुनर्जन्म और न उसका फल दाता ईश्वर । इसलिये वर्तूतमान जीवन में ऐन्द्रियिक भोग प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस दर्शन-सम्प्रदाय को लोकायत अर्थात् लोक पर आश्रित दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि साधारणतया मनुष्य अपने स्वाभाविक व्यवहार में इसी सिद्धान्त को मान कर चलते हैं। आत्मा और परमात्मा या परलोक आदि तत्त्वों को बुद्धिमान् मनुष्यों ने सीधे मनुष्यों को बहका कर उनके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध कराने के लिये निकाला है। इस दार्शनिक सम्प्रदाय का प्रवर्तृतक बृहस्पति नामक कोई आचार्य माना जाता है जिसके विषय में हमारी कोई अधिक जानकारी नहीं है।

इस सम्प्रदाय का कोई विशेष अलग दार्शनिक ग्रन्थ नहीं है। सारे दर्शन-सम्प्रदायों के संग्रह ग्रन्थों में, जैसे सर्वदर्शन-संग्रह आदि में ही इसका वर्णन पाया

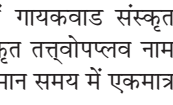
जाता है। परन्तु अभी हाल में गायकवाड संस्कृत सीरीज में एक ग्रन्थ जयर्षिभट्टकृत तत्त्वोपप्लव नाम का प्रकशित हुआ है जो कि वर्तमान समय में एकमात्र इस सम्प्रदाय का ग्रन्थ है।

18- जैन दर्शन

यहां पर हम जैन धर्म के विषय में कुछ न कहकर केवल जैन दर्शन के उस मूल तत्त्व की ओर सङ्केत करेंगे जो कि जैन दर्शन की भारतीय दर्शन को देन है।

यह ऊपर (1. परि0 10) बताया जा चुका है कि भूल से पहिले पाश्चात्य विद्वानों ने बौद्धधर्म और जैन धर्म में अन्तर नहीं किया था, परन्तु उनमें कतिपय समतायें होते हुए भी उनकी दार्शनिक प्रक्रिया में मौलिक भेद है। अर्थात् बौद्ध अनात्मवादी और जैन वैदिक दर्शनों के अन्तर्गत हैं। वे आत्मा और बाह्य वस्तुओं को द्रव्य के रूप में मानते हैं।

क्रमशः ...



बेहतर विकल्प एवं जरूरी मुद्दों का अभाव ही विपक्ष की अक्षमता

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहां कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और कोई भी विपक्ष हमेशा के लिए विपक्ष नहीं रहता। सत्ता के लंबे कार्यकाल के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति उकताहट पैदा होती है। लेकिन उकताहट और सत्ता परिवर्तन के बीच एक बड़ा अंतर है। मतदाता किसी सरकार से नाराज हो सकता है, उसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है, फिर भी केवल नाराजगी के आधार पर किसी ऐसे विकल्प को स्वीकार नहीं करता, जिसके पास देश के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा न हो, जो सत्ता का लालची एवं बेहतर विकल्प से वंचित हो। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने मूल प्रश्न यही है-क्या वह केवल सरकार से असंतुष्ट है या जनता के सामने कोई विश्वसनीय विकल्प भी रख रहा है? राहुल गांधी लंबे समय से यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति अपेक्षित एंटी-इंकंबेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के कारण जनता की वास्तविक इच्छा सामने नहीं आ पा रही। इन आरोपों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत दावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है, उन्हें अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मानना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का निष्पक्ष और तथ्यात्मक उत्तर मिलना लोकतंत्र के हित में है।

इसी संदर्भ में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विवाद महत्वपूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग स्वयं एसआईआर-2026 से संबंधित मतदाता सेवाएं और मतदाता सूची उपलब्ध करा रहा है तथा वह अपने को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बताता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती मिली है। इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक नारों से नहीं, संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा। यहीं विपक्ष की राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव आयोग के विरुद्ध आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत ढंग से हटाया गया है तो उसका विरोध



होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा केवल आयोग के विरोध से नहीं होगी। लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब विपक्ष जनता को यह भी बताए कि सत्ता मिलने पर वह शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शहरी जीवन, कानून-व्यवस्था और प्रशासन में क्या बदलेगा।

यही वह बिंदु है जहां ‘वोट चोरी’ का राजनीतिक विमर्श जनता के रोजमर्रा के सवालों से टकराता है। एक सामान्य परिवार को बच्चों की महंगी शिक्षा की चिंता है। रोजगार की बदलती प्रकृति, एआई और नई तकनीक के कारण पारंपरिक कौशल तेजी से अप्रासंगिक हो रहे हैं। डिग्री लेने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाएं युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में युवा यह जानना चाहता है कि अगली सरकार परीक्षा व्यवस्था को कैसे विश्वसनीय बनाएगी, स्कूलों की गुणवत्ता कैसे सुधारेगी और बदलती तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए करोड़ों युवाओं को तैयार कैसे करेगी। किसान की समस्या की केवल एमएसपी या आंदोलन तक सीमित नहीं है। फसल आने पर कीमत गिर जाती है और कुछ महीने बाद वही प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसका समाधान केवल विरोध में नहीं, बल्कि गांव-कस्बे तक भंडारण, कोल्ड-चेन, प्रसस्करण, कृषि बाजार और मूल्यवर्धन की मजबूत व्यवस्था में है। विपक्ष यदि कृषि सुधारों का विरोध करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि वह वैकल्पिक कृषि ढांचा किस तरह खड़ा करेगा।

रोजगार का प्रश्न इससे भी बड़ा है। भारत की युवा आबादी को उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नई तकनीक से जोड़ना होगा। निवेश के लिए स्थिर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचंद कारोबारी वातावरण जरूरी है। केवल बड़े उद्योगपतियों पर राजनीतिक

खान से संगीत की शुरुआती शिक्षा ली थी। फिर साल 1965 में जगजीत सिंह परिवार को बिना बताए मुंबई आ गए थे।

काफी ज्यादा संघर्ष के बाद जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में गाने का मौका मिला था। साल 1967 में जब जगजीत सिंह काम ढूंढ रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात चित्रा दत्त से हुई। हालांकि उस दौरान चित्रा शादीशुदा थीं। लेकिन इसके बाद भी जगजीत और चित्रा एक-दूसरे को दिल दे बैठे और दिसंबर 1969 में चित्रा ने अपने पति को तलाक लेकर जगजीत सिंह से शादी कर ली।

बता दें कि जगजीत सिंह और चित्रा पंडित छगन लाल शर्मा और उस्ताद जमाल

प्रहार या संपत्ति की गणना जैसे नारों से रोजगार पैदा नहीं होते। विपक्ष यदि संपत्ति के पुनर्वितरण या सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसे साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति और अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। ‘जितनी आबादी, उतना हक’ जैसी राजनीति सामाजिक

प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सामने लाती है, लेकिन आज की चुनौती प्रतिनिधित्व के साथ-साथ क्षमता निर्माण की भी है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसर मिलें-यह सामाजिक न्याय का अधिक स्थायी आधार है। केवल आंकड़े गिनना पर्याप्त नहीं, उन आंकड़ों के पीछे खड़े मनुष्य का जीवन बदलना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में ममता बनर्जी की भूमिका विशेष चर्चा का विषय बनी है। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर नया विमर्श अवश्य उभरा है। हाल की इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने विपक्ष का दायरा बढ़ाने और व्यापक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा संकट केवल भाजपा से मुकाबला नहीं, बल्कि उसके भीतर का परस्पर अविश्वास है। सीटों का बंटवारा, क्षेत्रीय वर्चस्व, नेतृत्व का प्रश्न और राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर साथ आना आसान नहीं है। आज की स्थिति में आप का चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से अलग रहकर अपना रास्ता अपनाना भी इस अंतर्विरोध को दिखाता है।

कांग्रेस, तुणमूल, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राजद, आप और दूसरे क्षेत्रीय दल जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीति करते हैं, तब राष्ट्रीय मंच पर उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है? जनता इसी का उत्तर चाहती है। चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी यही कसौटी लागू होती है। इंडिया गठबंधन ने 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग तक मार्च सहित विरोध कार्यक्रम घोषित किए हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। यह आंदोलन संवैधानिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला सकता है। लेकिन यदि विपक्ष का पूरा राजनीतिक अभियान केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित रह गया, तो इससे चुनावी संस्थाओं पर व्यापक विश्वास का

प्रश्न हल नहीं होगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मतदाता सूची, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और चुनावी पारदर्शिता को लेकर वह कौन से संस्थागत सुधार करेगा।

बड़ा प्रश्न है कि सत्ता की पात्रता को विकसित करने के लिये विपक्ष क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सकारात्मक राजनीति को बल देती। वास्तव में विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दों को समाधान में बदलने की क्षमता का है। बेरोजगारी है, शिक्षा का संकट है, कृषि की समस्या है, स्वास्थ्य का खर्च है, महंगाई की चिंता है, शहरी प्रदूषण है, एआई से बदलती नौकरियां हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है। जनता इन सबको प्रतिदिन महसूस करती है। लेकिन राजनीतिक विमर्श बार-बार मोदी बनाम नौन, राहुल बनाम मोदी, ईवीएम बनाम बैलेट और आयोग बनाम विपक्ष की बहस में सिमट जाता है। भारतीय मतदाता सरकार से मोहभंग होने पर भी यह देखता है कि उसके सामने विकल्प क्या है। वह जमीन छोड़कर अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाता। उसे ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकार की कमियां गिनाने के साथ अपनी क्षमताएं भी बताए, जो केवल सत्ता की आलोचना नहीं, शासन का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे, जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो अपनी चुनावी पारदर्शिता की कसौटी भी सामने रखे, जो सामाजिक न्याय की बात करे तो शिक्षा और अवसर का रास्ता भी बताए, जो उद्योगपतियों से सवाल करे तो निवेश और रोजगार की अपनी नीति भी स्पष्ट करे।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, विपक्ष की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सत्ता से मोहभंग लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस मोहभंग को राजनीतिक परिवर्तन में बदलने के लिए विश्वसनीय विकल्प चाहिए। आज इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती भाजपा और नरेंद्र मोदी से लड़ने से बड़ी है-उसे जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना है कि उसके पास भारत के अगले दशक की कोई स्पष्ट, ठोस और क्रियान्वित करने योग्य कहानी भी है। विपक्ष यदि यह विश्वास पैदा कर पाया तो चुनाव आयोग का मुद्दा भी लोकतांत्रिक सुधार की सार्थक बहस बनेगा, ममता बनर्जी की भूमिका भी सार्थक होगी और राहुल गांधी के सवाल भी व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेंगे।

बेटे के गम ने बना दिया गजल सम्राट जगजीत सिंह को दर्द का बेताज बादशाह

अनन्या मिश्रा

गजल के बेताज बादशाह जगजीत सिंह ने संगीत की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी, जो समय की सीमाओं को पार करके आज भी उतनी ही ताजा हैं। आज ही के दिन यानी की 10 अक्तूबर को जगजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जगजीत सिंह के लिए संगीत सिर्फ उनका शौक नहीं बल्कि आत्मा की आवाज थी। उन्होंने कम उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त कर ली थी। 1970 के दशक में गजल को एक खास वर्ग का संगीत माना जाता था, तब जगजीत सिंह ने इसको आम जनमानस की जुबान बना दिया। वह अपने गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे।

राजस्थान में 08 फरवरी 1941 में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने पंडित छगन लाल शर्मा और उस्ताद जमाल



से पद्म भूषण से नवाजा गया था।

देसीउत्पाद खोजें

चित्रा और जगजीत का एक बेटा विवेक था। वहीं 20 साल की उम्र में विवेक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को बुरी तरह से तोड़ दिया था। इस घटना के बाद जगजीत सिंह संगीत की

समय तक वह गजल किंग बन चुके थे। जगजीत ने प्राइवेट एलबम के साथ फिल्मों में भी कई गजलें गाईं जिनमें अर्थ, जिस्म, प्रेम गीत, तुम बिन, जॉर्ज्स पार्क जैसी फिल्में शामिल हैं। जगजीत सिंह को साल 2003 में भारत सरकार की ओर

से पद्म भूषण से नवाजा गया था। देसीउत्पाद खोजें चित्रा और जगजीत का एक बेटा विवेक था। वहीं 20 साल की उम्र में विवेक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को बुरी तरह से तोड़ दिया था। इस घटना के बाद जगजीत सिंह संगीत की

दुनिया से दूर हो जाना चाहते थे। उन्होंने कई महीनों तक गाना नहीं गाया। लेकिन फिर उन्होंने संगीत की दुनिया में धीरे-धीरे वापसी की। लेकिन उनकी पत्नी चित्रा सिंह ने रियलयरमेंट ले लिया। बेटे की मौत का सदमा सीने में दबाए बैठे जगजीत सिंह जब वापस गजल गायकी की दुनिया में लौटे, तो उनकी आवाज में किसी को खोने का दर्द कई गुना बढ़ा हुआ था।

साल 2011 में यूके में जगजीत सिंह को गुलाम अली के साथ परफॉर्म करना था। लेकिन इससे पहले उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, 23 सितंबर 2011 को जगजीत सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह करीब दो सप्ताह तक कोमा में रहे और इस दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। वहीं 10 अक्तूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

आज का इतिहास

- 1756 ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः कब्जे के लिए मद्रास से कूच किया।
- 1846 ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की।
- 1868 क्यूबा ने स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह किया।
- 1910 वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- 1924 शिकागो में स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना की गई।
- 1942 सोवियत संघ ने आस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की।
- 1964 टोकियो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया।
- 1970 फिजी ने स्वतंत्रता हासिल की।
- 1971 अमेरिका के एरिजोना के लेक हवासु शहर में लंदन ब्रिज को पुनर्निर्मित किया गया। इसे ब्रिटेन से खरीदकर तोड़कर अमेरिका लाया गया था।
- 1978 रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी।
- 1986 सैन सल्वाडोर में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 1,500 लोगों की मौत।
- 1990 अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से लौटा।
- 1991 भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब जीता।
- 1992 दूसरा हुगली पुल 'विद्यासागर सेतु' खुल।
- 1999 सन् 2006 में राष्ट्रकुल खेल मेलबोर्न में कराये जाने की घोषणा।
- 2000 श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री सिरीमाओ भंडारनायके का निधन।
- 2001 बांग्लादेश में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।
- 2003 भारत ने इझायल रूस के साथ एवाक्स निर्माण के लिए समझौता किया।
- 2004 ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जान हावर्ड की भारी जीत।
- 2005 एंजेल मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
- 2008 निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- 2014 भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा।
- 2022 प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव निधन हुआ था।

भाजपा हैरान, पुलिस परेशान, क्या है राहुल गांधी की धप्पा पॉलिटिक्स!

अभिनय आकाश

संसद से चुनाव आयोग तक का रास्ता छवनी में तब्दील था, चप्पे-चप्पे पर भारी बैरिकेडिंग और अलर्ट मोड में खड़ी पुलिस लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर सबको धप्पा दे दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा खोलते हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अचानक आकाशवाणी भवन की ओर रुख किया और सीधे 8 घंटे की नाकाबंदी कर डाली। प्रशासन देखता ही रह गया और राहुल का यह सरप्राइज अटेक पूरी तरह कामयाब रहा। पिछले दो महीनों में यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी के इस पलैश प्रोटेस्ट ने दिल्ली पुलिस ही नहीं, खुद अपनी पार्टी के नेताओं तक के होश उड़ा दिए हैं। पिछले दो महीनों में यह तीसरी बार है जब राहुल ने अचानक धरना देकर पुलिस और कुछ हद तक कांग्रेस नेताओं को भी चौंका दिया है।

जुलाई में, कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर अचानक विरोध प्रदर्शन किया। पिछले महीने, उनकी नई रणनीति का दूसरा चरण तब देखने को मिला जब वह अचानक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक छात्र प्रदर्शनकारी के साथ घुस गए; इस छात्र को 20 जुलाई की हिंसा के दौरान पैलेट गन से चोट लगी थी और राहुल ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल का यह नया सियासी प्लेबुक अब विरोधियों के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित सिरदर्द बन चुका है!

सड़कों पर अचानक होने वाले ऐसे विरोध-प्रदर्शन राहुल के राजनीतिक हथियारों में एक नया हथियार बन गए हैं। मंगलवार को इसका तीसरा चरण देखने को

मिला। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली पुलिस को विपक्ष के निर्वाचन सदन तक मार्च करने की हर चाल का पहले से अंदाज़ा था। जब विपक्ष का मार्च ईसीआई हेडक्वार्टर से कुछ सौ मीटर दूर नीति आयोग के दफ्तर के पास पहुँचा, तो प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हुआ। इस गहमागहमी के बीच, राहुल ने कैमरों को तस्वीर लेने का मौका दिया। जब कांग्रेस नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब वह पुलिस बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और तिरंगा लहराया। हालाँकि, पुलिस का सन्न जवाब दे गया। इसके बाद वही जाना-पहचाना नज़ारा देखने को मिला; पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना और उन्हें बसों में भरना शुरू कर दिया।

प्रियंका गांधी एक बस में सवार हुईं, जो आकाशवाणी भवन के पास खड़ी थी। राहुल भी बस में चढ़ने ही वाले थे। तभी हालात बदल गए। टीओआई और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही राहुल बस में चढ़ने वाले थे, उन्होंने प्रियंका को कोई इशारा किया। जल्द ही, वायनाड के सांसद नीचे उतरे और गांधी भाई-बहन तेज़ी से आकाशवाणी भवन की ओर दौड़ पड़े। इस अचानक उठाए गए कदम से न सिर्फ़ पुलिस, बल्कि कांग्रेस नेता भी हैरान रह गए। आकाशवाणी भवन के गेट के पास कोई पुलिसकर्मी नहीं था। सुरक्षा गार्डों ने गांधी भाई-बहन को रोकने की कोशिश की, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, लेकिन आखिरकार दोनों परिसर में दाखिल हो गए। पुलिस को उम्मीद थी कि लोगों को हिरासत में लेने से विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक बदले हालात ने एक नया धरना शुरू कर दिया। इस अफरातफरी के बीच राहुल ने पत्रकारों से कहा कि देश



के साथ जो किया गया है, वह देशद्रोह है।

चाहे पीएम मोदी हों, अमित शाह हों या ज्ञानेश कुमार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह पता नहीं चल पाया है कि गांधी भाई-बहन ने अचानक आकाशवाणी भवन में घुसने का फ़ैसला क्यों किया। हो सकता है कि राहुल निर्वाचन सदन जाने के लिए शॉर्टकट के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल करना चाहते हों, क्योंकि निर्वाचन सदन आकाशवाणी भवन के पिछले गेट के पास ही है। हालाँकि, पुलिस ने तुरंत पिछला गेट बंद कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों को आकाशवाणी भवन के परिसर में ही घंटों तक धरना देना पड़ा। राहुल और प्रियंका ब्रॉडकास्टिंग हाउस के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ गए।

केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी समेत कांग्रेस के दूसरे नेता भी आकाशवाणी के गेट से अंदर घुसने में कामयाब रहे, जबकि पुलिस बल को तैनात करने की कोशिश कर रही थी। बाकी लोगों को बाउंड्री वॉल पर चढ़ते और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की

मांग करते हुए नारे लगाते देखा गया। कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाने में ज़रा भी देर नहीं की। पार्टी ने एक्स पर राहुल के अचानक रास्ते से हटकर कहीं और जाने का एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ मज़ाकिया अंदाज़ में धप्पा कैप्शन लिखा था। यह ड्रामा सूरज ढूबने के काफी देर बाद तक चलता रहा। जब कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मिले बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया, तो उनके लिए रोल और एनर्जी ड्रिंक्स मंगवाए गए। इससे एक और विवाद खड़ा हो गया। आप इसके बारे में यहां पढ़ सकते हैं। रात करीब 8 बजे, पुलिस ने आखिरकार आकाशवाणी भवन परिसर को खाली कराना शुरू किया। तस्वीरों में राहुल को परिसर से खींचकर बस की ओर ले जाते हुए देखा गया। नेताओं को किंग्सवे कैप पुलिस स्टेशन ले जाया गया और हिरासत में रखा गया, जिसके बाद रात 10 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया।

यह पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने प्रशासन को चकमा दिया हो। 21 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों का एक दल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास पहुंच गया और बिना किसी पूर्व सूचना के धरने पर बैठ गया।इस अचानक हुए प्रदर्शन से पहले खुद कांग्रेस सांसदों को भी अंधेरे में रखा गया था। उन्हें शुरुआत में केवल यह कहकर बुलाया गया था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हों। जैसे ही सभी नेता एकत्र हुए, उन्हें

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास



साथ बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी ने राजनीतिक टकराव को और तीखा कर दिया। देर रात सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक हुए सड़क पर उतर आए, तो यह केवल किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं रह जाया, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास है। अगर यह विश्वास खो गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खो जायेगा? इस पर लोकतंत्र के चौकीदारों को सोचा पड़ेगा समझना पड़ेगा? जनता के अंदर यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका वोट सुरक्षित है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, उसने इस बहस को और तेज कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के मार्च की धुरी बने और विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया। इसके बाद सड़क पर धरना, हिरासत और फिर आकाशवाणी भवन परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा तथा अन्य नेताओं का करीब नौ घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आया। राहुल गांधी की हिरासत और उनके

आयोग तक मार्च करने से रोक दिया गया और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध को किस सीमा तक रोका जाए, यह भी लोकतंत्र की परिपक्वता की कसौटी है। विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, तब आयोग को इसे केवल राजनीतिक बयान मानकर खारिज करने के बजाय जनता के सामने अधिकतम पारदर्शिता के साथ तथ्यों को रखना चाहिए। इसी तरह विपक्ष की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना उसका अधिकार है, लेकिन गंभीर आरोपों के साथ ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी भी है। वोट चोरी जैसा आरोप सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं है। यह करोड़ों मतदाताओं के विश्वास और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसलिए यदि विपक्ष के पास प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक और संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखना चाहिए। केवल नाओं और राजनीतिक आक्रोश से लोकतंत्र की विश्वसनीयता मजबूत नहीं हो सकती। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के सवालों को देशविरोध या लोकतंत्र विरोध के चरमों से देखने से बचना होगा। लोकतंत्र में अलसहमिति व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यदि विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व है कि वे सवालों का जवाब दें। सवालों से बचने के बजाय पारदर्शिता के जरिए संदेह दूर करना अधिक प्रभावी रास्ता है। मंगलवार का घटनाक्रम इस दृष्टि से भी चिंताजनक है कि देश की संसद से निकले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन

अमेरिका-ईरान की जंग का सारी दुनिया में प्रभाव

सनत जैन

इजरायल, फिलिस्तीन, रूस, यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हुआ युद्ध मिडिल ईस्ट के कई देशों तक फैल गया है। धीरे-धीरे करके इसका असर अब सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने 8 महीने पहले दावा किया था, एक सप्ताह के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। एक सप्ताह छोड़ 8 माह निकल गए हैं, युद्ध खत्म होने के स्थान पर बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की दखलंदाजी देखने को मिल रही है। डॉलर मुद्रा को भी चुनौती मिलना शुरू हो गई। अमेरिका ने तरह-तरह से टैरिफ लगाकर दुनियां को हैरान किया वहीं होर्मुज बंदरगाह में कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इसका असर सारी दुनिया में पड़ने लगा है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई सारी दुनिया के देशों में बढ़ रही है। सभी जगह आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक मंदी की आशंका से सारा विश्व इन दिनों भयाक्रांत है। इसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग अपने अहंकार के चलते युद्ध समाप्त हो इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि वह पूरे विश्व में शांति बनाए रखें, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं। युद्ध में केवल लड़ने वाले देशों को नुकसान होता हो ऐसा नहीं है। अमेरिका को 3.3 अरब डॉलर का नुकसान ईरान के साथ इस युद्ध में हो चुका है। उसके 15 जेट विमान मार गिराए गए हैं। एफ 16 विमान, 81 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और बड़ी संख्या में ड्रोन नष्ट हुए हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका ने जो सैन्य अड्डे बनाए थे वह लगभग बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका को ईरान के साथ इस युद्ध में भारी आर्थिक एवं सामरिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद भी मरता क्या ना करता की तर्ज

पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर माह में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए इस युद्ध को ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां विनाश ही विनाश है। अमेरिका में तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता मात्र 30 फीसदी रह गई है। टैक्सास जैसे राज्य से यह मांग उठने लगी है, रिजर्व भंडार से डीजल की आपूर्ति की जाए। अमेरिका जैसा देश डीजल की कमी से अब जूझने लगा है। इस युद्ध में उसके हथियार भंडार से 70 फीसदी हथियार युद्ध में काम आ चुके हैं अब उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं है। इसके बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है, उल्टे रूस को लेकर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, इसका असर दुनिया के कई देशों में पड़ने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डों पर भी अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंध के डर से काम करना बंद कर दिया है। इसका असर अडानी जैसी कंपनियों पर पड़ने लगा है। 1993 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर सारी दुनिया के आर्थिक और सामाजिक विकास का जो ढांचा तैयार होने का सपना देखा गया था वह इतनी जल्दी बिखर जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं कोई काम की नहीं रह जाएंगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। जब सारी दुनिया संकट में फंसी हुई है इसके बाद भी कहीं से कोई आवाज नहीं निकल रही है। दुनिया के देशों में जिस तरह से महंगाई और पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गई है, रूस खस्ते यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बगावत जैसी स्थिति पर पहुंच सकती है। एक बार भीड़ सड़कों पर आ गई तो मुसीबत होगी, भीड़ तंत्र को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। समय रहते दुनिया के देशों को वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए एक बार फिर विचार विमर्श करना होगा।

सौरभ वार्ण्य

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुनाव प्रणाली और जनता का मताधिकार है। सत्ता बदलने का अधिकार जनता के पास है और इसी अधिकार की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करती है। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, मतदाता सूची की शुद्धिता को लेकर संदेह पैदा हो और विपक्ष चुनाव प्रणाली में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हों तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खो जायेगा? इस पर लोकतंत्र के चौकीदारों को सोचा पड़ेगा समझना पड़ेगा? जनता के अंदर यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका वोट सुरक्षित है।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, उसने इस बहस को और तेज कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के मार्च की धुरी बने और विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया। इसके बाद सड़क पर धरना, हिरासत और फिर आकाशवाणी भवन परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा तथा अन्य नेताओं का करीब नौ घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आया। राहुल गांधी की हिरासत और उनके

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत

एम वैंकैया नायडू

मैंने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन खास लोगों में से हैं, जो विरासत में मिली चुनौतियों को चुपचाप स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है, और उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया भी है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसे हल न किया जा सके, भले ही समय के साथ वे समस्याएं कितनी भी जटिल या मुश्किल क्यों न हो गई हों।

मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘चलता है!’ वाली सोच से हटकर ‘बदल सकता है!’ वाली सोच अपनाने की बात कही थी। यह बात मुश्किल समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण के एक अहम पहलू को दिखाती है। वह समस्याओं से समझौता करने में विश्वास नहीं रखते। इसके बजाय, वह कदम-दर-कदम स्थिति को बदलने का काम करते हैं। मैं नरेंद्र भाई मोदी को पहले पार्टी संगठन में और बाद में सरकार में एक सहकर्मी के तौर पर जानता हूं। हममें से जो लोग दशकों तक भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे हैं, उनके लिए अनुच्छेद 370 और राम जन्मभूमि कोई मामूली राजनीतिक मुद्दे नहीं थे। लेकिन, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि कुछ पल ऐसे भी आए, जब हमारे अपने कार्यकर्ताओं को भी यह शक होने लगा था कि क्या वे अपने जीवन में कभी इन मुद्दों का समाधान होते देख पाएंगे। लेकिन, नरेंद्र भाई मोदी ने इसे संभव कर दिखाया।

जब वह अक्तूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो राज्य उसी साल आए भूकंप की तबाही से जूझ रहा था। मोदी जी समझ गए थे कि सबसे पहला काम लोगों का भरोसा बहाल करना है। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली दिवाली गांधीनगर में मनाई जा सकती थी। इसके बजाय, उन्होंने इसे कच्छ में भूकंप से प्रभावित परिवारों के साथ मनाया। वर्षों तक चली उनकी नीतियों ने कच्छ को नए सिरे से खड़ा होने में मदद की। गुजरात में पानी की कमी एक स्थायी चुनौती थी। सरदार सरोवर परियोजना की योजना दशकों पहले बनी थी और इसकी आधारशिला 1961 में रखी गई थी। दशकों तक यह परियोजना उलझनों और देरी की शिकार रही। मोदी जी ने कई वर्षों तक मुश्किलों के



बावजूद इस परियोजना को आगे बढ़ाया और आखिरकार यह सुनिश्चित किया कि बांध बनकर तैयार हो और नर्मदा का पानी गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचे।

2014 में, नरेंद्र भाई मोदी तब प्रधानमंत्री बने, जब भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था और बैंकिंग प्रणाली कई तरह की समस्याओं से घिरी हुई थी। उन्होंने इन समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। बहुत-से लोगों का मानना था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी राजनीतिक सहमति कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन, मोदी जी की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की बदौलत ऐसा संभव हुआ। आज, हम भारत को डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में नंबर एक के तौर पर देखते हैं। लेकिन, यह भी चुनौतियों से पार पाकर ही हुआ है। कई अनुभवी नेताओं ने मजाक में पूछा था कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले को डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में कैसे शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवहार में यह बदलाव संभव कर दिखाया।

गरीबी एक अन्य ऐसी समस्या थी, जिसे भारत ने स्थायी मान लिया था। आज, 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। अगर हम पंच पुरस्कारों की बात करें, तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन्हें पहचान नहीं मिली, उन्हें पहचान मिले और जो लोग चुपचाप, बिना दिखे काम कर रहे थे और हकदार थे, उन्हें देखा जाए और अहमियत दी जाए। 2014 के बाद, हमारे

देश के गुमनाम नायकों को हर साल नागरिक सम्मानों की सूची में जगह मिली।

कई दशकों तक, नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या बना रहा, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति अपनाकर, लगभग छह दशकों से चली आ रही इस समस्या को अब प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सबसे अहम बात यह नहीं है कि हर समस्या गायब हो गई है, बल्कि यह है कि उन्होंने समस्याओं के सामने असहाय महसूस करने की पुरानी सोच को खत्म कर दिया है। कोविड-19 महामारी के समय, दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ा। लेकिन, नरेंद्र भाई मोदी ने एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने और टीकाकरण अभियान, दोनों ही समय में देश को एकजुट रखा। कई अन्य बड़े देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से पटरी पर वापस लौटी।

हाल ही में पश्चिम एशिया में आए संकट ने ऊर्जा सुरक्षा, पोट परिवहन और व्यापार से जुड़ी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन, सरकार और समाज को साथ लेकर चलने वाला भारत का दृष्टिकोण परिपक्व और जिम्मेदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एक नारा लोकप्रिय हुआ है, जो इस बदलाव को बखूबी बयां करता है- ‘मोदी है, तो मुमकिन है।’ इसे भारत के राजनीतिक बदलाव में भी देखा जा सकता है। भाजपा को एक ऐसी पार्टी माना जाता था, जो कुछ खास भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों तक ही सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत जैसे क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार और गरीबों, ग्रामीणों व वंचित समुदायों के बीच पार्टी का बढ़ता समर्थन देश के राजनीतिक मानचित्र को बदल चुका है।

जिन्होंने उनके सफर को करीब से देखा है, वे जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी यह सोचकर शुरूआत नहीं करते कि मौजूदा हालात क्या इजाजत देते हैं। वह यह सोचकर शुरूआत करते हैं कि देश को किस चीज की जरूरत है और फिर उसे पूरा करने के लिए जरूरी हालात बनाते हैं। यह सोच उस देश के लिए बेहद जरूरी है, जो 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनना चाहता है।

उत्तर प्रदेश में चमत्कार के भरोसे विपक्ष

शैलेश कुमार

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच एक छद्म युद्ध चल रहा है। विधानसभा का अगला चुनाव कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर हवा में तीर फेंके जा रहे हैं। कभी कोई कांग्रेसी फरमान देता है कि 150 से एक भी कम नहीं, तो कोई समाजवादी चुनौती देता है कि 25 से ज्यादा लेकर दिखाओ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पी.डी.ए. अर्थात् पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के दम पर भाजपा को पछाड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि सपा के बिना उसका गुजारा नहीं, फिर भी उसे ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के पुराने गठजोड़ के दिन वापस लौटने की उम्मीद है। विपक्ष की तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान और ब्राह्मण के 2006 वाले समीकरण की वापसी की उम्मीद में जी रही है, जब उसे किसी बड़ी पार्टी को साथ लिए बिना विधानसभा में बहुमत मिल गया था। तीनों ही पार्टियां मोदी-योगी युग में 2017 के बाद बदले हालात से बेखबर नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि अति पिछड़े और अति दलितों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ खिसक चुका है और उसके बिना कोई चुनाव जीतना आसान नहीं। यही तीन पार्टियां हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे सकती हैं। चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होंगे। करीब 6 महीने का ही समय बचा है लेकिन अब तक विपक्षी पार्टियों की कोई रणनीति सामने नहीं आई। पिछले चुनावों के नतीजे साफ बताते हैं कि अकेले दम पर भाजपा को चुनौती देना किसी एक पार्टी के बस में नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों के नेता अपने व्यक्तिगत दंभ के शिकार हैं या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद में जी रहे हैं। कांग्रेस और सपा 2022 का विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ीं। कांग्रेस ने प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 399 पर उम्मीदवार उतारे लेकिन जीती महज 2 सीटें। 387 यानी लगभग 97 प्रतिशत सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो

गई। कांग्रेस को कुल लगभग 2.4 प्रतिशत वोट मिले। समाजवादी पार्टी 347 सीटों पर लड़ी और 111 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसकी सहयोगी छोटी-छोटी पार्टियों को भी 14 सीटें मिलीं। बसपा सभी 403 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 290 यानी लगभग 72 प्रतिशत सीटों पर उसके उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस एक साथ आ गई तो नतीजे बदल गए। इस चुनाव में प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी और 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी और 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। बसपा 79 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ीं, तब बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थीं। इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा को असली चुनौती सपा, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन ही दे सकता है और उसकी संभावना बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में हार जीत के फैसले में लंबे समय तक अल्पसंख्यक मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी करीब 19 प्रतिशत मुसलमानों की है। कांग्रेस, बसपा और सपा को सबसे ज्यादा उम्मीद अल्पसंख्यकों से है। लेकिन उनका वोट हर बार बंट जाता है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से अल्पसंख्यकों का मोहभंग हो चुका है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में ए.आई.एम.आई.एम. का प्रवेश चुनाव के पहले भ्रम फैलाने के लिए काफी है। ये पार्टी चुनाव जीतती नहीं लेकिन गैर भाजपा उम्मीदवारों के लिए माहौल खराब जरूर करती है। पसमांदा यानी गरीब वर्र के मुसलमानों को अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश आकामयाब हो चुकी है। अब भाजपा उसे इस्तेमाल करके विपक्षी वोट को बांटने की कोशिश में जुटी है। एम.बाई. यानी मुसलमान-यादव गठबंधन भी अब चुनाव जिताने का फार्मूला नहीं रह गया।



शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है कुंजल क्रिया

भारत में योग का चलन आज से नहीं बल्कि सदियों से रहा है। योग महज एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। बल्कि यह जीवन को सरल और बेहतर बनाने का एक बेजोड़ तरीका है। आज हम आपको योगा की एक ऐसी ही टैक्निक से रूबरू कराएंगे। जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को तो बाहर निकालती ही है। साथ ही आपको कई दूसरे लाभ भी देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुंजल क्रिया के बारे में। यह अन्य योगासन से बहुत भिन्न है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस क्रिया में आपको उल्टी करनी होती है। हा शायद यह आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन कुंजल क्रिया सही मायने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस क्रिया के बारे में।

क्या है कुंजल क्रिया

कुंजल क्रिया आपके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकालने की एक जबरदस्त टैक्निक है। कुंजल क्रिया के बारे में सबसे पहले हठयोग से संबंधी एक प्रदीपिका ग्रंथ में दिया गया था। इस ग्रंथ में ही इसे शरीर की सफाई करने की तकनीक के रूप में बताया गया है। कुंजल क्रिया न केवल आपके शरीर को साफ करती है बल्कि यह आपके मन को भी नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इसे लेकर एक शोध भी प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि उल्टी करने के बाद व्यक्ति को खालीपन महसूस होता है और इससे कई शारीरिक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कैसे की जाती है कुंजल क्रिया।

कैसे होती है कुंजल क्रिया

- इसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 गिलास गुनगुने पानी की जरूरत होगी और हर एक लीटर पानी पर एक चम्मच सेंधा नमक या साधारण नमक भी चाहिए होगा।
- अब आपको एक लीटर पानी में एक चम्मच सेंधा नमक मिलाना होगा और कगासन की मुद्रा में बैठना होगा।
- इसके बाद आपको इसी मुद्रा में यह पानी जल्दी से जल्दी पीना होगा और उल्टी करने के लिए थोड़ा आगे झुक कर खड़ा होना होगा।
- जब आपको लगे की पेट खाली हो चुका है तो शवासन की मुद्रा में 30 मिनट के लिए लेट जाए।
- इस क्रिया में आपको उल्टी तुरंत आ जाती है। ऐसे में अगर यह क्रिया करें तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें।

वजन और पाचन के लिए

जब भी आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और फेट कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप फैट या वजन कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो य क्रिया आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यह पाचन तंत्र को पूरी तरह स्वस्थ रखने काम काम करती है।

तनाव और चिंता से राहत

जब आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है और आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। इससे आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुंजल क्रिया के जरिए तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह क्रिया किसी विशेषज्ञ की

या फिर आपकी आयु 16 साल से कम है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें।

खांसी और सर्दी से राहत

जब आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती है और इनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही इसके जरिए आपके फेफड़े भी साफ हो जाते हैं और आपके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। इस तरह यह सर्दी और खांसी के लक्षणों से राहत दिलाती है।



मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमारी आंखों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। जिससे लोगों में सिरदर्द, जलन और आंखों में तनाव के मामले बढ़े हैं। खासकर, एलईडी और टीएफटी स्क्रीन से निकलने वाली सफेद रोशनी आंखों को तनाव में डालती है। आयुर्वेद के अनुसार, संपूर्ण शरीर की तरह आंख की तत्वों से संबंधित है। आंख की मांसपेशियां पृथ्वी तत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि ब्लड वेसल्स अग्नि द्वारा और आंखों का रंग हवा से नियंत्रित होता है।

सुबह उठकर मुंह में पानी भरें

रोज सुबह उठकर टॉयलेट जाने से पहले या बाद में मुंह में पानी भरें और कुछ सैकंड्स तक होल्ड करें। इस दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अब कुल्ला करें दें और इस प्रक्रिया को दो से 3 बार दोहराएं।

त्रिफला वॉटर का उपयोग करें

त्रिफला वॉटर आई वॉश आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह न केवल आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि आंखों की चमक में भी सुधार करता है। खासतौर से थकी हुई आंखों को आराम देने का यह बेहतरीन तरीका है।

स्वस्थ आंखों के लिए षटकर्म करें

आयुर्वेद में शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने, उसे मजबूत बनाने और रोगमुक्त बनाने के लिए 6 यूरीफिकेशन टेक्नीक

ऐसे करें आंखों की देखभाल

के बारे में बताया गया है। इनमें से नेती और ट्राटक सूखी आंखों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे आयुर्वेदिक उपाय के रूप में काम करते हैं। बता दें कि ट्राटक षटकर्म आंख का व्यायाम है जिसमें किसी भी बिंदु पर आंखों को स्थिर करके निरंतर देkhना होता है।

बरतें ये सावधानियां

- आंखों की देखभाल के दौरान कभी भी बहुत तेज गर्म या फिर बर्फ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- अचानक तापमान में हुए परिवर्तन से बचने का प्रयास करें।
- अगर आपका शरीर गर्म हो रहा है या आप पसीने से तर हैं, तो अपने चेहरे और आंखों पर पानी के छीटें मारने से पहले 10 मिनट तक इंतजार करें। जब तक आपकी बॉडी सही तापमान में एडजस्ट न हो जाए, छीटें मारने से बचें।



- सुबह-शाम चेहरे पर पानी के छीटें मारें
- 10-15 बार अपनी आंखों और चेहरे पर टंडे या फिर नॉर्मल पानी के छीटें मारें। इस प्रक्रिया को आप तब भी दोहराएं, जब शाम को काम से वापस घर लौटें। ऐसा करने से आंखों को बहुत आराम मिलेगा।

स्वस्थ आंखों के लिए फायदेमंद है अंजन

स्वस्थ आंखों के लिए अंजन का उपयोग बहुत फायदेमंद है। अंजना एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पलकों के अंदरूनी हिस्से पर लगाते हैं। बता दें कि अंजना जड़ी-बूटियों से बना एक गाढ़ा आईलाइनर है। इसे कोलिरिसम भी कहते हैं। इसका उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंख से जुड़ी अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। हालांकि, यह काजल की तरह दिखता है, लेकिन इससे काफी अलग है। इसे मिनरल्स और जड़ी-बूटियों को पीसकर पेस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है यहाँ एक्सपर्ट द्वारा बताए गए तरीकों से आपको आंखों की सही देखभाल करने में मदद मिलेगी।

साइलेंट किलर है तनाव, इसे गंभीरता से लेना है बहुत जरूरी

जिन लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब रेट दिया है, उनकी मात्रा पैडेमिक आने के बाद तीन गुना बढ़ गई है। ओरेकल और वर्क प्लेस इंटेलिजेंस जैसी कंपनियों द्वारा एक हालिया सर्वे जिसमें 11 देशों के 12000 लोगों ने भाग लिया ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव में एम्प्लॉय के बदले ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए गए हैं। 53% ने माना की उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज पैडेमिक के

क्या कहती है रिपोर्ट ?

इस कड़ी में लगभग 39% लोगों को घर से वर्चुअली काम करने में दिक्कत आई। वहीं 34% को वर्क कल्चर के ना होने की कमी खली। वहीं 29% लोगों को नई तकनीकों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ कंपनी के सीनियर अधिकारी वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ और हेल्थी वर्क कल्चर को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं आज भी मेंटल हेल्थ को एक स्टीरियोटाइप के तौर पर देखा जाता है। कंपनी में ओपन कम्युनिकेशन और समपोर्ट की कमी खलती है। कंपनी के लीडर को अपने स्टीफ को न सिर्फ इंस्पायर करना चाहिए ताकि वे अपनी बात को खुलकर शेयर कर सकें, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे कोच या थेरेपिस्ट से मदद भी ले सकें। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, अगर तनाव से संबंधी कोई भी लक्षण नजर आता है तो तत्काल डॉक्टर से मिलना है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते।



वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से पड़ता है सेहत पर बुरा असर

देश में दिवाली आने वाली है और इस माह में लोगों द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्मॉग का रूप ले लेता है। इस तरह के पॉल्यूटिड स्मॉग में धूल और वायु प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक आदि हानिकारक मिश्रण रहते हैं। जो खांसी, गले में खराश, छाती में जलन, रिकन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण, आंख व नाक में एलर्जी के अलावा इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बनाते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक शोध आया है जिसमें चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। नए शोध के अनुसार, वायु प्रदूषण और सड़क यातायात के शोर के संपर्क में आने से हृदय गति रुकने का खतरा बढ़ सकता है। शोध का रिजल्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक ओपन-एक्सेस जर्नल ‘जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन’ में प्रकाशित किया गया था। इसलिए आपको वायु प्रदूषण से खुद को सेफ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

खतरों का कारण बना। उन्होंने आगे कहा, हम आश्चर्यचकित थे कि कैसे दो पर्यावरणीय कारक – वायु प्रदूषण और सड़क यातायात शोर ने एक साथ हृदय गति रुकने का जोखिम बढ़ा दिया है। शोध में पता चला है कि रोड ट्रैफिक की तुलना में एयर पॉल्यूशन हर्ट फेलियर के खतरे की मजबूत वजह बना। हालांकि, इन हर्ट फेलियर वाली 30 प्रतिशत नर्सों में हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी।

सांस लेने में तकलीफ

वायु प्रदूषण की वजह से बुजुर्ग लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर पॉल्यूशन के कारण बुजुर्गों के शरीर के कई अंग धीमी गति से कार्य करते हैं और इसी तरह का हाल फेफड़ों का रहता है। क्योंकि लॉन्स प्रदूषित हवा को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाते हैं जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है।

आंखों में परेशानी

वायु प्रदूषण के चलते कई बार बच्चों से लेकर बुजुर्गों की आंखों में भी दिक्कतें आती हैं। दूषित हवा के कण हमारी आंखों में एलर्जी पैदा करने लगते हैं जिससे कई बार हमें आस-पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। साथ ही धूल मिटटी से आंखों में खुजली भी होती है।

सेहत संबंधी दिक्कतें

बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है जिसकी वजह से उनको वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से उनका दम घुटने लगता है। वे इस वातावरण को आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। इसके चलते कई दफा, छीकआना, छाती में जलन, रिकन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण और गले में खराश जैसी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।



जान भी ले सकती है लौकी

लौकी का सेवन करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे कई प्रकार से खा सकते हैं। सब्जी, जूस, खीर, कलाकंद, परांटे सहित अन्य तरीकों से इसका सेवन किया जा सकता है। इसका सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्या में राहत मिलती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम,

कड़वी लौकी का सेवन करने से आपकी जान पर बात बन सकती

नौबत आ जाती है। इसलिए भूलकर भी कड़वी लौकी का सेवन नहीं करें। लौकी का जूस बनाने से पहले इसे जरूर टेस्ट करें। अगर वह कड़वी लगती है तो इसका सेवन नहीं करें। कड़वी विषैली लौकी का सेवन करने के नुकसान- बेचैनी, घबराहट, ब्लड प्रेशर की समस्या, उल्टी होने लगती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार अंगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में अंग फैल भी हो सकते हैं। इसलिए भूलकर भी लौकी को टेस्ट किए बिना इसका प्रयोग नहीं करें। कड़वी लौकी की पहचान उसे चखकर की जा सकती है। बता दें कि इसे पकाने पर भी कड़वापन खत्म नहीं होगा। कड़वी लगने

डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेती है। जिससे उसमें केमिकल विकसित हो जाता है। तो कई बार तापमान कम ज्यादा होने पर भी यह बदलाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर भी ऐसा हो सकता है।

मस्क के पोस्ट पर राहुल की प्रतिक्रिया पर भाजपा हमलावर

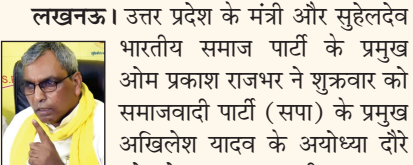
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा स्टारलंक पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा है। सूर्या ने राहुल गांधी पर स्टारलंक के भारत में प्रवेश को लेकर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कंपनी का समर्थन कर रहे हैं। स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क द्वारा कंपनी के भारतीय बाजार में प्रवेश करने के प्रयासों पर की गई टिप्पणियों पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर तेजस्वी सूर्या ने आलोचना की। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के पहले के रुख को पलट दिया है। तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि कांग्रेस ने पिछले साल भारत में स्टारलंक के संभावित प्रवेश का विरोध किया था। उस दौरान उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि यह कदम प्रधानमंत्री के करीबी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से उठाया गया था।

कांग्रेस को पता नहीं किधर जाना है, बाएँ या दाएँ : सिंधिया



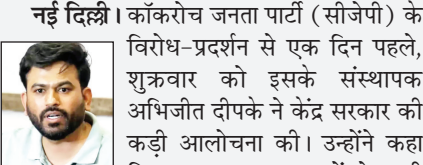
नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 अक्टूबर को भारत में स्टारलंक को काम करने का लाइसेंस देने के मामले में कांग्रेस पार्टी की राय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी साफ़ है और तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें एडिशन में बोलेते हुए सिंधिया ने कहा कि मैंने पहले ही सरकार का रुख और पॉलिसी साफ़ कर दी है। मैंने आपको बताया है कि तीन कंपनियों के पास लाइसेंस हैं, सिर्फ़ एक कंपनी के पास नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद पता है कि वे किस तरफ़ जा रहे हैं—बाएँ या दाएँ। शुरु में उन्हें किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने से दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फ़्रेमवर्क को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लाइसेंस धारकों को रेवेन्यू-शेयरिंग के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।

मुस्लिम वोट बैंक खोने के डर से अखिलेश रहते हैं परेशान



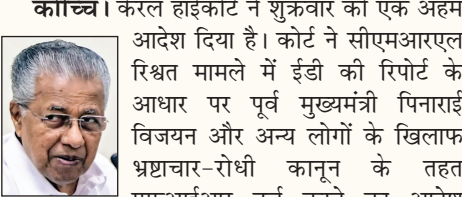
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला किया और उन पर वोट-बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि यादव इस बात को लेकर हिचकिचाते और परेशान रहते हैं कि अयोध्या जाने का उनकी मुख्य अल्पसंख्यक वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। राजभर ने कहा कि उन्हें अपने वोट बैंक को बचाय कि उनके कामों का मुस्लिम वोटरों पर क्या असर पड़ेगा, खुलकर राजनीति करनी चाहिए। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के निष्पक्ष कामकाज की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर लोगों को यह कहते हुए देखा है कि योगी जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता है।

दिल्ली में हमारा आंदोलन होकर रहेगा : दीपके



नई दिल्ली। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन से एक दिन पहले, शुक्रवार को इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं से डरती है, तो उसे पूरे देश को ही बंद कर देना चाहिए। यह बयान 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी आने-जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने के बाद आया है। इसके साथ ही कहा कि हमारा आंदोलन होकर रहेगा। सीजेपी ने चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है तो, फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है?

रिश्वत मामले में पूर्व सीएम पिनराई विजयन की बढ़ेगी मुसीबत?



कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सीएमआरएल रिश्तत मामले में ईडी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने वकील के. एम. शाहजहां की याचिका को मंजूरी दे दी। शाहजहां का तर्क था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर शुरुआती जांच करने के बजाय पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर विजयन, उनकी बेटी विना टी और उनके पति पी ए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ईडी का दावा है कि उसकी रिपोर्ट को शुरुआती जांच रिपोर्ट माना जा सकता है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार ने इस तर्क का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि एजेंसी की रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी नहीं है और इसके लिए शुरुआती जांच की जरूरत है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

जेवर एयरपोर्ट का नाम अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ करने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है।



काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी प्रधानमंत्री जैसे साधक की सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाकर पुनः स्थापित कराना भी प्रधानमंत्री के प्रयासों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय संबंध है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का

औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडव्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, किसानों को एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश में 65 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने, 3.67 करोड़ राशन के तहत मुफ्त खाद्यान्न देने और लाखों परिवारों तक नल से जल पहुंचाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रदेश में 6.08 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत के साथ टी20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को झटका



ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और जैक फाउल्क्स चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज चैपमैन पिछले महीने यूरोपीय टी20 लीग के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके बाएं पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और वह अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। तेज गेंदबाज फाउल्क्स के दाहिने कूल्हे में हाल ही में कैंटरबरी में अभ्यास सत्र के दौरान चोट लग गई थी। चैपमैन ने अब तक 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह 32 वर्षीय बल्लेबाज भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी कर सकता है लेकिन फाउल्क्स की वापसी की कोई निश्चित समयसीमा नहीं है।

ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को इन दोनों खिलाड़ियों के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने स्वीकार किया कि टी20 सीरीज से पहले दो प्रमुख खिलाड़ियों का चोटिल होना टीम के लिए बड़ा झटका है। वॉल्टर ने कहा, मार्क और जैक के लिए मुझे बहुत दुख है और मैं उनके शीर्ष स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमें खुशी है कि हम जोश और ब्लेयर की विशेषज्ञता का फायदा उठा सकते हैं। यह दोनों खिलाड़ी इस सीरीज में खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। टी20 सीरीज का आखिरी मैच एक नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड की टी20 टीम- मिचेल सैंटरन (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफ़ी, लॉकी फर्ग्युसन, मेट हेनरी, बेवन किक्स, काइल जैमीसन, एडम मिलने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड की टी20 टीम- मिचेल सैंटरन (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफ़ी, लॉकी फर्ग्युसन, मेट हेनरी, बेवन किक्स, काइल जैमीसन, एडम मिलने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर।

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर 21 वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में 6 अक्टूबर 2026 का दिन भारत के लिए केवल आर्थिक उपलब्धि या घरेलू राजनीतिक टकराव का दिन नहीं रहा, बल्कि यह दिन दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र की संस्थागत शक्ति, संवैधानिक परिपक्वता और न्यायिक संयम,तीनों को एक साथ परखने वाला दिन बन गया। एकऔर पश्चिम एशिया सहित दुनियाँ के अनेक हिस्सों में युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव,ऊर्जा असुरक्षा औरआर्थिक अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं,वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक ने अपने ताजा आकलन में वित्त वर्ष 2026– 27 के लिए विकास दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है।

साथियों, भारत की आर्थिक कहानी आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। जब अनेक विकसित और

सैंसेक्स 879 अंक चढ़ा निफ्टी 22,548 पर बंद

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन तूफानी तेजी देखने को मिली। बाजार के बैचमार्क इंडेक्स करीब डेढ़-डेढ़ फीसदी उछलकर बंद हुए। बाजार की तेजी को आईटी, एफएमसीजी सेक्टर ने लीड किया। ब्रॉड मार्केट में मिडकैप इंडेक्स में भी चमक रही। जबकि वॉलिलैटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX 6 फीसदी से ज्यादा टूट गया, जो 14.35 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को मजबूत रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 879 अंक चढ़कर 72,569 और निफ्टी 316 अंक बढ़कर 22,548 पर बंद हुए। टीसीएस के नतीजों से बेहतर उम्मीदों के चलते आईटी शेयरों ने तेजी की अगुआई की। एफएमसीजी और ऑटो शेयर भी चढ़े, जिससे अन्य सेक्टरों में भी खरीदारी का संकेत मिला। मिडकैप में 1.66 फीसदी की बढ़त रही। वहीं, इंडिया VIX 5.37 फीसदी गिरकर 14.46 पर आ गया।

शाकाहारी थाली 10% और नॉन-वेज 6% महंगी

नई दिल्ली। महंगाई का असर अब आम लोगों की रसोई के बजट पर साफ दिखाई देने लगा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ‘रोटी राइस रेट’ रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में घर पर तैयार होने वाली शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़ गई। वहीं, मांसाहारी थाली भी 6 फीसदी महंगी हुई है। सब्जियों, खाद्य तेल, चावल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का खर्च बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल सितंबर में शाकाहारी थाली तैयार करने की लागत 28.1 रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 30.8 रुपए हो गई। इसी तरह, मांसाहारी थाली की कीमत 56 रुपए से बढ़कर 59.5 रुपए पहुंच गई। अगस्त की तुलना में सितंबर में वेज थाली 4 फीसदी और नॉन-वेज थाली 3 फीसदी महंगी हुई। रसोई के बजट पर सबसे अधिक असर प्याज की बढ़ती कीमतों का पड़ रहा है।

दूसरी तिमाही नतीजों के बाद टीसीएस का शेयर 5.5% उछला

नईदिल्ली। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का शेयर सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद फोकस में है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन लगभग अनुमान के मुताबिक रहे। सीसी टर्म में आय में पहली तिमाही के मुकाबले 0.5 फीसदी, सालाना आधार पर 2.8 फीसदी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 15 फीसदी बढ़कर 13884 करोड़ रुपये रहा। लेकिन मार्जिन 24 फीसदी पर सपाट रही। लेकिन मैनेजमेंट की ओर से स्पष्ट गाइडेंस नहीं मिला। नतीजतन, शेयर पर एनालिस्ट्स की राय बंट गई नजर आ रही। दूसरी तिमाही नतीजों के बाद टीसीएस के शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को कारोबारी सेशन के दौरान टीसीएस का शेयर एनएसई पर 5 फीसदी से ज्यादा उछला, जो 2194 रुपये तक चढ़ा।

कैंसर की दवाएं होंगी 70 प्रतिशत तक सस्ती

नई दिल्ली। भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं की बिज्जी और सप्लाई पर मुनाफे को अधिकतम खुदरा मूल्यके 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। सरकार के इस बड़े कदम से कैंसर की दवाइयों की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की भारी कमी आएगी। इससे देश भर के कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी और उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हर एक लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं।

भारत की 7.1 प्रतिशत की विकास दर से दुनियाँ चौकी

विकासशील अर्थव्यवस्थाएं युद्ध, ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान,महंगाई और भू- राजनीतिक तनाव से जूझ रही हैं,तब विश्व बैंक द्वारा भारत को विकास दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत करना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वैश्विक निवेशकों और आर्थिक संस्थानों के लिए भारत की अतर्निहित क्षमता पर भारीसा का संकेत है। अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने एफ्वाय 2026– 27 के लिए 6.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया था; अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया गया। मजबूत घरेलू मांग, उद्योग और सेवा क्षेत्र की गति तथा आर्थिक सुधारों की निरंतरता भारत की विकास कहानी के महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। हालांकि कृषि और मानसून से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए 7.1 प्रतिशत का अनुमान भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण जरूर है, लेकिन यह भी



याद दिलाता है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों, खाद्य महंगाई और भू-राजनीतिक संकटों से सुरक्षा के लिए आर्थिक नीतियों को लगातार गतिशील बनाए रखना होगा।

साथियों इसी आर्थिक उपलब्धि के समानांतर भारत के लोकतांत्रिक संस्थागत ढांचे को लेकर एक गंभीर राजनीतिक बहस भी सामने आई। 6 अक्टूबर को आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग की ओर मार्च किया। विपक्ष की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर

प्रक्रिया को वापस लेने की रही।

साथियों, आज जब दुनियाँ के अनेक हिस्सों में युद्ध की आशंका,राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत संकट दिखाई दे रहे हैं,भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सात प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास बनाए रखने की नहीं है। चुनौती यह भी है कि आर्थिक विकास के साथ लोकतांत्रिक विश्वास, चुनावी पारदर्शिता, न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा समान गति से आगे बढ़े।विश्व बैंक का 7.1 प्रतिशत अनुमान भारत की आर्थिक क्षमता का उत्साहजनक संकेत है,लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर उठे प्रश्न और न्यायपालिका के संयमपूर्ण फैसले यह भी याद दिलाते हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल सकल घरेलू उत्पाद में नहीं मापी जाती।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का

अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 6 अक्टूबर 2026 का भारत दुनिया को एक बहुआयामी संदेश देता है, अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास, लोकतंत्र में बहस और न्यायपालिका में संयम। यही तीनों मिलकर किसी आधुनिक राष्ट्र की वैश्विक प्रतिष्ठा को स्थायी बनाते हैं। भारत की आर्थिक गति यदि निवेश और रोजगार को मजबूत करती है,लोकतांत्रिक संस्थाएं यदि जनता के विश्वास को बनाए रखती हैं और न्यायपालिका यदि संविधान की रक्षा करते हुए नीति-निर्माण की उचित सीमाओं का सम्मान करती है, तो भारत की वैश्विक साख केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि उसकी संस्थागत परिपक्वता से भी मजबूत होगी।लुद्ध और अनिश्चितता से घिरी दुनिया में यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है,विकास की गति के साथ लोकतंत्र की गहराई और संविधान की गरिमा।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के द्वितीय बैच के 36 युवाओं से मुख्यमंत्री ने किया आत्मीय संवाद

युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी से ही होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण: विष्णु देव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के द्वितीय बैच के प्रतिभागियों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं के सवालों के जवाब दिए और अपने छात्र जीवन, संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर जनसेवा और सार्वजनिक जीवन की यात्रा के अनुभव उनके साथ साझा किए। उन्होंने युवा फेलो से कहा कि वे इस अवसर का उपयोग केवल शासन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए ही नहों, बल्कि अपने ज्ञान, कौशल और नवीन विचारों के माध्यम से जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं के पास शिक्षा, ऊर्जा, प्रतिभा और नए विचारों की शक्ति है। जब यह शक्ति जनकल्याण और समाज की बेहतरी से



जुड़ती है तो बड़े परिवर्तन का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर परिश्रम और प्रत्येक दायित्व का निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन सफलता के साथ आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करता है।

संवाद के दौरान युवा प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री श्री साय से फेलोशिप को लेकर उनकी अपेक्षाओं, सुशासन, शिक्षा, रोजगार, निवेश, आधुनिक तकनीक, प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका और उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन की यात्रा से जुड़े अनेक प्रश्न किए।

निवेश को रोजगार में बदलना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के रोजगार और उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में परिवर्तित करना है। निवेश समझौतों के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है। अपने हाल के सिंगापूर प्रवास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा, विविध नोएपज और मजबूत औद्योगिक संभावनाएं विकास को नई गति देने में सक्षम हैं।

शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल भी जरूरी

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं के लिए शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल को आवश्यक बताते हुए कहा कि बदलती अर्थव्यवस्था और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। जिलों में लाइवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के 30 आईटीआई का उन्नयन कर उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग ढाई वर्षों में 700 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 24 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक नियोकाओं ने भाग लिया और लगभग पांच हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

जीएसटी प्रशासन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को मिला प्रतिनिधित्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन की आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा कर प्रशासन में सुधार के लिए अपनाई गई तकनीकी पहलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टींडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। इससे प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया।



अधिक सरल, सटीक और परिणामोन्मुख बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और अन्य डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में विभिन्न पहल की गई हैं। इन तकनीकी नवाचारों का उद्देश्य कर संबंधी आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण करना, कर अनुपालन में सुधार लाना, संभावित कर अनियमितताओं की समय पर पहचान करना तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।

1 नवंबर से 3358 रुपए प्रति बिंक्टल की दर से धान खरीदी शुरू करे सरकार: कांग्रेस

रायपुर। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि खरीफ की फसल तैयार होने को है लेकिन सरकार की तैयारी कहीं दिख नहीं रही है। न बारदानों की व्यवस्था, न सोसायटियों की फंड, न भुगतान के लिए बजट, न परिवहन का टैंडर छत्तीसगढ़ के किसान आज भाजपा सरकार की वादाखिलाफी और तानाशाही नीतियों का दंश झेल रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के दौरान बजट प्रावधान के बावजूद खरीफ सीजन 2022-23 की चौथे किस्त का 1700 करोड़ रुपया दबाकर बैठी साय सरकार। सरकार किसानों के पैसे का ब्याज खा रही है या खजाना खाली हो चुका है? अब जबरिया रकबा समर्पण का चिनीना खेल, खेल रही है ताकि किसानों से कम धान खरीदना पड़े। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट चेतावनी देती है कि 1 नवंबर से 3358 रुपये प्रति किंटल की दर से धान खरीदी शुरू की जाए और किसानों का एक-एक पैसा तुरंत जारी हो, वरना कांग्रेस हर जिले में सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन की अगुवाई करेगी।

नीति आयोग की महानिदेशक छिब्बर ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के कार्यों की सराहना की

रायपुर। नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने कम समय में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने राज्य में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके वास्तविक परिणामों के आकलन के लिए एक सशक्त एवं स्थायी निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र विकसित करने पर जोर देते हुए इस दिशा में डीएमईओ, नीति आयोग की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।



राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ में आज स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने की। इस अवसर पर सचिव, योजना श्री भुवनेश यादव सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर का स्वागत करते हुए कहा

कि राज्य नीति आयोग एक परामर्शदात्री एवं ज्ञान आधारित संस्था (थिंक टैंक) के रूप में प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहा है। आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और विभागीय समन्वय के क्षेत्र में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं।

श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तथा उनके प्रभाव और परिणामों का आकलन ठोस आँकड़ों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाए।

भारत व जिम्बाब्वे महिला टी-20 मैचों की तैयारियां अंतिम दौर में

रायपुर। इसी माह जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली महिला टी20 मैचों के लिए शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम 11 अक्टूबर और जिम्बाब्वे की महिला टीम 12 अक्टूबर रायपुर पहुंचेगी।

तीन मैचों का पहला मुकाबला 16 और अंतिम मुकाबला 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैचों के टिकट बुकिंग 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। क्रिकेट प्रेमी दर्शक अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन टिकट इंजन मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं। यह जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने आज संयुक्त पत्रकारवाता के दौरान दी। पत्रकारवाता में संघ के अध्यक्ष वी मोहनदास, विजय शाह ने बताया हर यूजर ज्यादा से ज्यादा छह (6) टिकट ही खरीद सकता है। कोई भी टिकट ऑफ़लाइन नहीं बेचे जाएंगे। केवल ऑनलाइन डिजिटल टिकट ही दिए जाएंगे। बुकिंग पूरी होने के बाद, फेंस अपने ऐप पर डिजिटल टिकट/क्यूआर कोड पा सकते हैं। मैच के दिन गेट पर क्यूआर कोड दिखाकर फेंस स्टेडियम में एंटी कर सकते हैं।



भाजपा के राज में महंगी बिजली व बिजली कटौती हो रही : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की कुप्रबंधन और लापरवाही से छत्तीसगढ़ में बिजली का संकट भी पैदा हो रहा है। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य को बिजली बेचा जाता था। आज हमें दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ रही है। भाजपा सरकार महंगी बिजली बेच रही है, स्मार्ट मीटर से लूट रही, अब बिजली उत्पादन भी नहीं कर पा रही है। उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों को छत्तीसगढ़ बिजली बेचना था, आज छत्तीसगढ़ को बिजली खरीदने की नौबत आ गयी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटे बिजली गोल हो जाती है। भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी।



नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की पहचान

रायपुर। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए गुरुकुल महिला महाविद्यालय, का राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर नशा मुक्त युवा संवाद मेला का आयोजन चंगोराभाटा के सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा नशामुक्त परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस दौरान युवाओं ने नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर, लाखे नगर मंडल अध्यक्ष सचिन सिंघल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर, रमेश ठाकुर कुला प्रथक सहायक, संदीप कुलदीप, परमात्मा वस्त्रकार कल प्रथक सहायक उपस्थित रहे।

जिला सगठक एवं कार्यक्रम की संयोजक डॉ. रात्रि लहरी ने कहा कि तथा आज युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और सामाजिक जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस चुनौती का सामना केवल कानून से नहीं, बल्कि जागरूकता, सकारात्मक संवाद, पारिवारिक सहयोग और सामुदायिक सहभागिता से किया जा सकता है।

सरकार बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा रोजगार मेला लगवाकर प्राइवेट कंपनियों में 10 हजार की नौकरी दिलवा कर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि प्रदेश में 5 सालों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगे। आज प्रदेश के सरकारी विभागों में लगभग 1 लाख दस हजार से अधिक पद खाली है। अकेले शिक्षा विभाग में 57 हजार पद खाली है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ के 18 हजार से अधिक पद खाली हैं, उच्च शिक्षा विभाग में 3700 पद खाली है, पीडब्ल्यूडी में 6 हजार पद खाली है, सहकारिता विभाग में 4000, पीएचई 35, वन विभाग में 6000, जेल में 1200, ग्रामीण विकास में 8000, पुलिस विभाग में 7000, आदिम जाति कल्याण 7 हजार पद खाली है। सरकार यदि इच्छाशक्ति दिखाये तो एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में एक माह के अंदर रख सकती है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 5 सालों में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, तीन साल में पांच हजार भी नहीं। भाजपा को सरकार में आए पौने तीन साल हो गया है जब भाजपा सरकार में आई है।



अतिक्रमण के खिलाफ एनएचआई की सख्त कार्रवाई

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) द्वारा अतिक्रमण एवं अनाधिकृत प्रवेश मार्गों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रिंग रोड नंबर-1 पर तेलीबांधा स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास की अवैध एंट्री को बंद कर दिया गया है। वहीं, रिंग रोड के भाटागांव क्षेत्र में भी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने सार्वजनिक सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अनाधिकृत प्रवेश मार्गों को हटाने की कार्रवाई लागू नियमों एवं सक्षम न्यायालयों के संबंधित निर्देशों के अनुरूप की जाती है। इस संबंध में एनएचआई के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को सुगम बनाए रखना एनएचआई की प्राथमिकता है। अनाधिकृत प्रवेश मार्गों और अतिक्रमण के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।



राज्यपाल ने किया 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैम्पियनशिप का शुभारंभ

जूडो सिखाता है साहस, आत्मसंयम और अनुशासन का पाठ : डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जूडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि साहस, आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त माध्यम है। यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए जूडो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। राज्यपाल श्री डेका आज सरकंडा स्थित खेल परिसर में 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैम्पियनशिप-2026 का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बालक-बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वाधान में बिलासपुर जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 16 जिलो से 240 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक



भाग ले रहे है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि खेल हमें प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना, जीत में विनम्र रहना और हार से सीखकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी

भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित एशियाई खेलों और ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।

राज्यपाल ने कोंडगांव जिले की जूडो खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते

हुए कहा कि योगिता मंडावी को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने खेलेो इंडिया नेशनल गेम्स और ओपन नेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। वहाँ रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समारोह में राज्यपाल श्री डेका ने जूडो में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले हेमवती नाग, अभिषेक जायसवाल, कुमारी शारदा गोस्वामी और योगिता मंडावी को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के तीसरे माले में संचालित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) वार रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण और खुदाई पर नियंत्रण तथा नागरिकों में नागरिक बोध (सिविक सेंस) विकसित करने से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए



समन्वित कार्ययोजना तैयार करने और विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

श्री बोरा ने आईटीएमएस वार रूम में तकनीकी संसाधनों, निगरानी व्यवस्था और उपलब्ध आंकड़ों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आईटीएमएस वार रूम में सेंटर फॉर गुड गवर्नंस के रूप में विकसित करने शहरी प्रबंधन, विभागीय समन्वय और नागरिक सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।